नवाचार

मंडला की दो ग्राम समितियों को मिला राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार, वन संरक्षण के कड़े नियमों से सुधरी जंगलों की सेहत

सामुदायिक वन क्षेत्र को बचाने बना दीं गहरी खाइयां

भानपुर खेड़ा, श्मशान घाट

छिछारी रैयत सामुदायिक वन क्षेत्र

मंडला, नवभारत। जनपद पंचायत बिछिया के अंतर्गत आने वाली दो ग्राम पर्यावरण समितियों ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर पूरे मध्य प्रदेश में जिले का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा घोषित वार्षिक जैव विविधता पुरस्कारों में जनपद बिछिया की ग्राम पर्यावरण समिति भानपुर खेड़ा को प्रदेश में द्वितीय और ग्राम छिछारी रैयत को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों समितियों को राज्य स्तर पर नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

जानकारी अनुसार दोनों ग्राम पर्यावरण समितियों की कार्यशैली अलग-अलग होते हुए भी बेहद प्रेरणादायक है। भानपुर खेड़ा समिति ने एक अनोखा नवाचार करते हुए गांव के खाली पड़े श्मशान घाट क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। समिति ने व्यापक वृक्षारोपण, आक्रामक खरपतवार प्रजातियों के नियंत्रण और कड़े नियम बनाकर श्मशान भूमि को एक जैव विविधतापूर्ण जीवंत वन क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए समिति को द्वितीय पुरस्कार के रूप में दो लाख रुपये की राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

बताया गया कि ग्राम पर्यावरण समिति छिछारी रैयत ने अपने सामुदायिक वन क्षेत्र को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। समिति ने आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के साथ मवेशियों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए गहरी खाइयों (ट्रेंच) का निर्माण किया। तकनीकी उपायों और कड़े नियमों को लागू कर उन्होंने उजड़ते वन को पुनर्जीवित कर दिया। इस सफलता के लिए समिति को तृतीय पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये की राशि और प्रमाण पत्र से नवाजा गया।

समितियों द्वारा बनाए गए ये कड़े नियम रहे रीढ़ की हड्डी

बताया गया कि ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से यह साबित किया कि जंगल केवल कहने भर से मां नहीं होता, बल्कि उसकी देखभाल करना समुदाय की जिम्मेदारी है। इसके लिए पेड़ काटने पर जुर्माना, चराई पर प्रतिबंध, घास काटने की छूट जैसे कड़े नियम लागू किए गए थे। एफईएस संस्था के प्रद्युमन आचार्य ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा बनाए गए कड़े नियमों से उन्हें आज यह सफलता मिली है। ग्रामीणों द्वारा बनाए गए इन नियमों में यदि कोई व्यक्ति पेड़ काटते पाया गया, तो उस पर पांच हजार रूपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही इसकी सटीक सूचना देने वाले सजग नागरिक को 500 रूपए का नकद इनाम देने का प्रावधान बनाया गया। इसके साथ ही वन क्षेत्र को नया जीवन देने के लिए 1 वर्ष तक मवेशियों के चराने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। वहीं हरियाली सुरक्षित रखने के साथ ग्रामीणों को राहत देने के लिए इस क्षेत्र से हाथ से घास काटकर चारे के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

पलायन में आई कमी, बढ़ा लघु वनोपज का उत्पादन

इन सामूहिक और सतत प्रयासों का सुखद परिणाम यह रहा कि गांवों से होने वाले रोजगार पलायन में भारी कमी आई है। वनों की सेहत सुधरने से महुआ, अचार, हर्रा-बहेड़ा जैसे लघु वनोपज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की आय बढ़ी है। बताया गया कि विगत वर्ष अक्टूबर 2025 में इन समितियों द्वारा अपने प्रस्तावों, सामूहिक कार्यवाहियों के दस्तावेजीकरण और वन संरक्षण से संबंधित वीडियो तैयार कर जनपद पंचायत बिछिया के माध्यम से राज्य स्तर पर आवेदन भेजे गए थे। इन अथक और जमीनी प्रयासों को आखिरकार राज्य स्तर पर बड़ी पहचान और सम्मान मिल गया है।

छात्रों ने अस्पताल और आईटी के कामकाज के सीखे गुर

सांदीपनी विद्यालय नारायणगंज के वोकेशनल छात्रों का 21 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित

नारायणगंज। शासकीय सांदीपनी विद्यालय नारायणगंज में संचालित वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थियों का 21 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। वर्ष 2016 से संचालित हेल्थ केयर एवं आईटी ट्रेड के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यक्षेत्र के वास्तविक वातावरण और कार्यशैली से रूबरू कराया गया।

हेल्थ केयर ट्रेड के छात्र-छात्राओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगंज सीबीएमओ डॉ. एएल कोल के कुशल मार्गदर्शन में अस्पताल के विभिन्न विभागों की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझा। व्यावसायिक प्रशिक्षक श्रीमती रुचि प्रदा संत की देखरेख में छात्रों ने अस्पताल के जनरल कक्ष, इंजेक्शन कक्ष, आई डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी लैब, दवा वितरण कक्ष, मलेरिया डिपार्टमेंट और ड्रेसिंग वार्ड में सक्रिय रहकर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण से छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र की बारीकियों को जमीनी स्तर पर समझने का अवसर मिला।

तीन अलग-अलग संस्थानों में आईटी छात्रों ने सीखीं तकनीकी बारीकियां-बताया गया कि आईटी ट्रेड के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण तीन अलग-अलग प्रतिष्ठित स्थानों पर व्यावसायिक प्रशिक्षक हेमंत पटेल की देखरेख में संपन्न हुआ। जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में छात्रों ने शासकीय कार्यालयों के काम-काज, जैसे ऑनलाइन डाटा एंट्री और ऑफिस फाइल मैनेजमेंट की व्यवस्था को सीखा। इसके साथ ही स्थानीय कम्प्युटर संचालक शौकत अली के मार्गदर्शन में छात्रों ने व्यावसायिक और कमर्शियल कार्य सीखे, जिनमें प्रिंट आउट निकालना, डाटा एंट्री, लेमिनेशन और ग्राहकों को ऑनलाइन डिजिटल समाधान प्रदान करना शामिल रहा। इसके साथ ही ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में संस्थान के संचालक उदय यादव, अंजलि और आयुषी के मार्गदर्शन में छात्रों को सीपीसीटी परीक्षा की तैयारी, हिंदी टाइपिंग और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर एडवांस कार्य करने का सघन प्रशिक्षण दिया गया।

संस्था प्रमुखों के मार्गदर्शन में मिली सफलता-व्यावसायिक प्रशिक्षक श्रीमती रुचि प्रदा संत ने बताया कि व्यवसायिक शिक्षा के तहत आयोजित यह पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय सांदीपनी विद्यालय नारायणगंज की प्राचार्या श्रीमती अर्चना नेमा की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती संगीता गुप्ता के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विद्यालय प्रबंधन ने सभी सहयोगी संस्थानों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया।

पड़रिया पंचायत की सड़क को लेकर उठ रहे तरह-तरह के सवाल

एक साल में उखड़ी सड़क, ग्रामीण बोले - क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित?

नारायणगंज। ग्राम पंचायत पड़रिया उर्फ नारायणगंज एक बार फिर चर्चाओं में है। जनपद मुख्यालय क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यालय से लोक सेवा केंद्र तक बनाई गई लगभग 150 मीटर लंबी सीसी सड़क निर्माण कार्य पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 4.62 लाख रुपये की लागत से बनी यह सड़क एक साल भी नहीं टिक सकी और जगह-जगह से गिट्टियां निकलने लगी हैं।

बताया जा रहा है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य खसरा नंबर 151/1/1 में 5वें वित्त आयोग मद से कराया गया था। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद यह सड़क आम नागरिकों, शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों की आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। लेकिन सड़क की वर्तमान हालत देखकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि जिस सड़क से प्रतिदिन अधिकारी-कर्मचारी और आमजन गुजरते हैं, वही सड़क यदि इतनी जल्दी टूटने लगे तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजिमी है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया या फिर गुणवत्ता की अनदेखी कर जल्दबाजी में काम पूरा कराया गया। स्थानीय लोगों के बीच अब यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इस गुणवत्ताहीन निर्माण के पीछे जिम्मेदार कौन है, निर्माण एजेंसी, पंचायत बॉडी या फिर किसी प्रकार का दबाव और कमीशनखोरी? ग्रामीणों का कहना है कि यदि मुख्यालय क्षेत्र में विकास कार्यों की यह स्थिति है तो दूरस्थ गांवों के हालात सहज ही समझे जा सकते हैं।

मामले में जब संबंधित उपयंत्री उपासना बघेल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि 'मिलकर बात करते हैं।' वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष आशाराम भारतीया ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कराने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

नारायणगंज में धड़ल्ले से बिक रही एक्सपायरी खाद्य सामग्री

कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति, ग्रामीणों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप

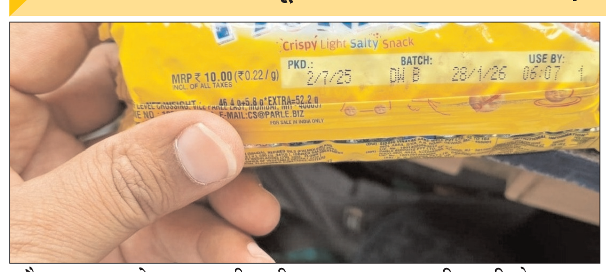

नारायणगंज, नवभारत। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नारायणगंज में इन दिनों एक्सपायरी डेट निकल चुकी खाद्य सामग्री की बिक्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर मुख्यालय होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदार और आम ग्रामीण रोजमर्रा की खाद्य सामग्री की खरीदी के लिए नारायणगंज बाजार पर निर्भर रहते हैं, लेकिन बाजार में खुलेआम एक्सपायरी सामान बिकने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की कई किराना दुकानों में समय-सीमा समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थ, पैकेज्ड आइटम और अन्य उपभोक्ता सामग्री रखी जाती है। आरोप है कि जांच के दौरान जिम्मेदार विभाग द्वारा केवल औपचारिकता निभाई जाती है, जिससे दुकानदार कार्रवाई से बच निकलते हैं और यह अवैध कारोबार लगातार जारी रहता है।

ग्रामीणों का कहना है कि जागरूकता की कमी के कारण आदिवासी एवं भोले-भाले उपभोक्ता पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट को समझ नहीं पाते और अनजाने में खराब सामग्री खरीद लेते हैं। कई बार ऐसी सामग्री के सेवन से लोगों की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल तक पहुंचने की स्थिति भी बन जाती है। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने आरोप लगाया कि यदि खाद्य सुरक्षा विभाग नियमित और निष्पक्ष कार्रवाई करे तो ऐसी स्थिति पर रोक लग सकती है। लेकिन विभागीय उदासीनता और कथित मिलीभगत के कारण उपभोक्ताओं की सेहत खतरे में पड़ रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों में विशेष अभियान चलाकर एक्सपायरी सामग्री जब्त की जाए, दोषी व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई हो।

प्रशासनिक अनदेखी पर नर्मदा रपटा पुल के गहरे जोड़ों को स्वयं ऑटो चालकों ने भरा

मंडला। नर्मदा नदी पर बने ऐतिहासिक रपटा पुल के जोड़ों पर बनी गहरी दरारें इन दिनों राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गई हैं। पुल के क्षतिग्रस्त जोड़ सड़क पर किसी खतरनाक ब्रेकर की तरह काम कर रहे हैं, जिससे गुजरने वाले वाहनों को भारी झटके लग रहे हैं। इसके कारण न सिर्फ वाहनों के कलपुर्जे टूट रहे हैं, बल्कि तेज रफ्तार वाहन अचानक अनियंत्रित भी हो रहे हैं, जिससे यहाँ किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है।

बताया गया कि पुल पर बने ये गड्ढे और दरारें इतनी गहरी हैं कि दुपहिया वाहन चालकों के लिए यह जानलेवा साबित हो रहे हैं। विशेष रूप से ऑटो चालक इन दरारों से अत्यधिक परेशान हैं, जिन्हें यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपने वाहनों की गति को अचानक बहुत धीमा करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों और चालकों ने बताया कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों को इस बदहाली से अवगत कराया, लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

महीने भर में दूसरी बार चालकों ने खुद की मरम्मत

प्रशासन की इस घोर अनदेखी के चलते हाल ही में कुछ स्थानीय ऑटो चालकों ने स्वयं ही सराहनीय पहल की है। उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च कर और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके इन गहरी दरारों को अस्थायी रूप से भरकर समतल किया। चालकों ने बताया कि इससे पहले एक माह पूर्व भी उन्होंने स्वयं कंक्रीट भरकर इन ज्वाइंट्स को दुरुस्त किया था, लेकिन भारी और लगातार यातायात के चलते कंक्रीट उखड़ गया। वर्तमान में पुल के कई हिस्सों से डामरीकरण भी पूरी तरह उखड़ चुका है।

श्रमदान करने वाले ऑटो चालकों का कहना है कि उनके द्वारा किया गया प्रयास केवल एक तात्कालिक राहत है। पुल की तकनीकी सुरक्षा और सुचारु यातायात के लिए इन क्षतिग्रस्त जोड़ों की लोक निर्माण विभाग द्वारा विशेषज्ञता के साथ पक्की मरम्मत करना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार किए बिना इस पुल की सुध ली जाए।

करौंदा टोला में द्रौपदी धुर्वे के घर पहुंचे कलेक्टर

बढ़ाया दिव्यांग छात्रा का हौसला, कहा-उच्च शिक्षा में नहीं आने देंगे बाधा

मवई। जहाँ हौसले बुलंद हों, वहाँ शारीरिक अक्षमता भी सफलता की राह नहीं रोक सकती इस प्रेरणादायक सत्य को ग्राम करौंदा टोला भीमडोंगरी की प्रतिभाशाली दिव्यांग छात्रा द्रौपदी धुर्वे ने साकार कर दिखाया है। द्रौपदी ने पैरों से लिखकर कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। द्रौपदी की इस असाधारण उपलब्धि से प्रभावित होकर कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे स्वयं उनके निवास पहुँचे। उन्होंने छात्रा एवं उसके परिजनों से आत्मीय चर्चा कर द्रौपदी के साहस, आत्मविश्वास और संघर्षशीलता की सराहना की तथा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कलेक्टर श्री धोटे ने द्रौपदी को आश्वस्त किया कि आर्थिक या अन्य किसी भी कारण से उसकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री धोटे ने द्रौपदी के पिता से परिवार की स्थिति और उपलब्ध शासकीय सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने आवास, राशन कार्ड एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की जमीनी स्थिति समझी तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से मुर्गी पालन जैसे स्वरोजगार से जुड़ने की सलाह भी दी गई। कलेक्टर श्री ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि द्रौपदी धुर्वे का परिवार शासन की किसी भी जनकल्याणकारी योजना से वंचित न रहे। उन्होंने पात्रता अनुसार सभी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जनपद पंचायत सदस्य अंतू राठौर, सहायक कलेक्टर शैलेंद्र चौधरी, तहसीलदार मवई, सीईओ जनपद पंचायत मवई सहित संबंधित अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

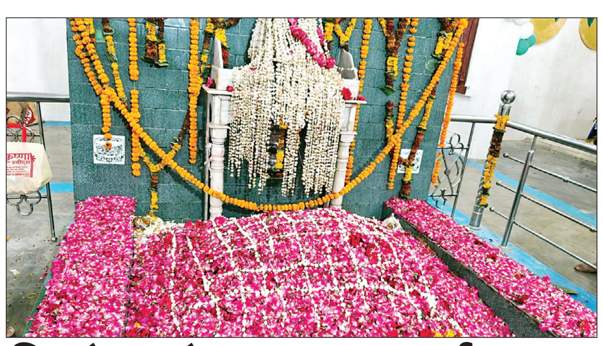

किले वाले बाबा का उर्स संपन्न

मंडला। हजरत बाबा बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैय किले वाले बाबा का उर्स हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उर्स की शुरुआत 20 मई को कुरआन खानी व मिलाद शरीफ से हुई। 21 मई को किले वाले बाबा का शाही संदल हजरत बाबा बंगाली शाह रहमतुल्लाह अलैय की दरगाह से मशहूर राजकुमार बैंड, सफेद घोड़ों का नृत्य, मलंग कला एवं आतिशबाजी के साथ शहर गश्त करता हुआ।

इस दौरान बाबा के चाहने वालों ने चादर पेश की। चादर पेश करने के बाद फातिहा हुई व मुल्क की तरक्की, अमन शांति व साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रहने की दुआ की गई। इस दौरान लंगर ए आम का एहतमाम भी किया गया। दरगाह में चादर पेश करने का सिलसिला चलता रहा। बाबा सैयद राहित अली, सिब्बल बाबा, जानू बाबा, शेबू बाबा, लड्डू बाबा, पप्पू सोनी, फारूक बाबा सहित कई मुजबीरों को हाजिरी हुई।

बाबा से मिलने फरियादियों का तांता लगा रहा। जबलपुर की मशहूर ताहिर शहनाई इस दौरान नातिया कलाम व क़व्वाली पेश करती रही। 23 मई की सुबह कुल की फातिहा से उर्स का समापन हुआ। उर्स को सफल बनाने में श्रीनाथ अग्रवाल, शशिकांत डोंगसरे, सैयद राहित अली, सिब्बल खान, मुन्नू गुप्ता, एडवोकेट अशोक वर्मा, नईम खान, अंकित मोनू अग्रवाल, रिंकू अग्रवाल, बबलू गुप्ता, संदीप मोदी, गोपाल बर्वे, महताब खान सहित सभी वर्ग के लोगों का उल्लेखनीय योगदान रहा।

अभियान

गणना के पहले दिन 306 और दूसरे दिन मिले 333 गिद्ध, कान्हा और फेन सेंचुरी में वैज्ञानिक पद्धति से हो रहा गणना कार्य

कान्हा, मुक्की, सरही और किसली रेंज में गिद्धों की दिखीं तीन दुर्लभ प्रजातियां

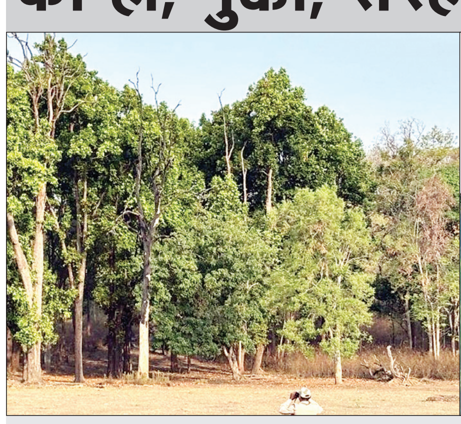

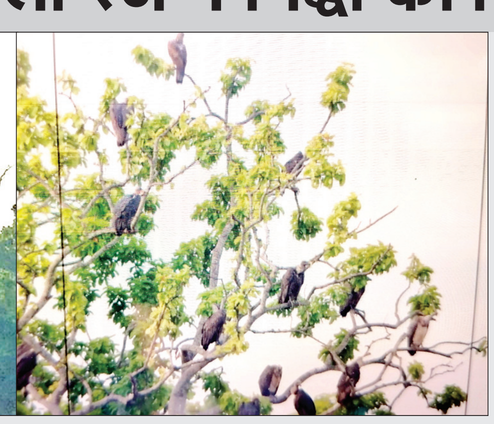

वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और प्रशिक्षित अमले से हो रही गणना

यह पूरी गणना वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के अनुसार की जा रही है। इसके लिए कान्हा के विशेष रूप से प्रशिक्षित मैदानी अमले और वनकर्मियों को तैनात किया गया है। इस वैज्ञानिक गणना का मुख्य उद्देश्य पार्क क्षेत्र में गिद्धों की सटीक संख्या, उनकी प्रजातिगत स्थिति, उनके घोंसलों के पैटर्न और उनके दीर्घकालिक संरक्षण और संवर्धन संबंधी महत्वपूर्ण डेटा बेस तैयार करना है।

मंडला। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में नेचुरल क्लीनर की भूमिका निभाने वाले गिद्धों की बढ़ती संख्या कान्हा के समृद्ध वातावरण के लिए एक अच्छी खबर है। बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना-2026 के दूसरे चरण ग्रीष्मकालीन गणना का कार्य कान्हा टाइगर रिजर्व में शुरू हो गया है। गिद्धों की घटती संख्या पर चिंता और उनके संरक्षण के उद्देश्य से कान्हा के कोर एवं बफर वनमंडल के साथ फेन वाइल्डलाइफ सेंचुरी के सभी 13 परिक्षेत्रों में यह तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन गणना के पहले दिन 306 और दूसरे दिन मिले 333 गिद्ध मिले है।

बताया गया कि गिद्धों की सटीक जानकारी और उनके आवासों के आकलन के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। गणना के लिए कान्हा के समस्त परिक्षेत्रों की 182 बीटों को शामिल किया गया है। पहले दिन सुबह 5.30 बजे से ही वन अमला पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गया। इस बार की गणना पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन और डेटा शीट का उपयोग किया जा रहा है जिससे गिद्धों की वास्तविक संख्या का सटीक डेटा प्राप्त हो सके।

दो दिन में 639 गिद्धों की हुई पहचान

गिद्ध गणना के पहले दिन प्राप्त जानकारी के अनुसार कान्हा, किसली, मुक्की और सरही परिक्षेत्रों में भारतीय गिद्ध और सफेद पीठ वाले गिद्ध प्रजातियों के कुल 306 गिद्धों को चिन्हित किया गया है। यह तीन दिवसीय गणना कार्यक्रम आगामी 24 मई तक निरंतर जारी रहेगा। अधिकारियों का मानना है कि यह गणना न केवल गिद्धों की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करेगी, बल्कि उनके संरक्षण की दिशा में भविष्य की रणनीतियां बनाने में भी मील का पत्थर साबित होगी। कान्हा प्रबंधन द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना के दूसरे दिन पार्क के विभिन्न परिक्षेत्रों में कुल 333 गिद्धों की उपस्थिति दर्ज की गई है। पार्क प्रबंधन से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह गणना कान्हा टाइगर रिजर्व के चार प्रमुख परिक्षेत्र कान्हा, मुक्की, सरही और किसली में एक साथ की जा रही है। शनिवार को द्वितीय दिवस के सर्वेक्षण के दौरान मुख्य रूप से गिद्धों की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियां कैमरे और दूरबीन में दर्ज की गईं। इनमें भारतीय गिद्ध, सफेद पीठ वाले गिद्ध और अत्यंत दुर्लभ माने जाने वाले राज गिद्ध शामिल हैं।

कुनबा बढ़ने के संकेत, 28 अवयस्क शावक भी मिले

दूसरे दिन गणना दल द्वारा किए गए सूक्ष्म और वैज्ञानिक अवलोकन के दौरान कुल दर्ज 333 गिद्धों में से 305 वयस्क पाए गए हैं। वहीं सबसे राहत की बात यह रही कि इस दौरान 28 अवयस्क यानी गिद्धों के बच्चे भी स्वस्थ अवस्था में दर्ज किए गए हैं, जो क्षेत्र में उनके सफल प्रजनन और बढ़ते कुनबे की ओर सकारात्मक संकेत करते हैं।

संरक्षण के लिए कान्हा प्रबंधन के सतत प्रयास

कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा गिद्धों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, उनके लिए भोजन की सुरक्षित उपलब्धता और बाहरी खतरों से बचाव के लिए निरंतर जमीनी प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की नियमित और ग्रीष्मकालीन गणनाओं से प्राप्त होने वाले आंकड़े भविष्य में गिद्धों के संरक्षण की नई कार्ययोजना और नीतियां बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।